श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैंने शुरू में ही उत्तर में कहा था कि सैलेरीज़ में 332 करोड़ बकाया है और जिसको statutory dues कहते हैं, वह 1762 करोड़ बकाया है। वह तीन साल से चला आ रहा है और हमारी कोशिश है कि मार्च तक सभी इम्प्लॉइज़ को पूरा बकाया मिल जाए।

Price of Cement

*264. SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) The role of Government in fixing the price of cement;

(b) whether there is any scope for fixation of cement rates by Government;

(c) whether Government are aware that the consumers are facing problems due to imbalance between demand and supply; and

(d) the steps proposed to be taken to increase the production?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (d) Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Cement is a fully decontrolled commodity and its prices are determined by market forces of demand and supply. The Government does not have any role in fixing the price of cement.

(c) The production and consumption of cement during the last three years and the current year in respect of large cement plants are given in the Statement below:—

(In Million Tonnes)

Year	Installed capacity	Capacity Utilization (%)	Pro-duction	Con-sumption (Domestic)	Exports
1999-2000	108.51	87	94.21	92.05	1.95
2000-01	114.52	82	93.61	90.29	3.15
2001-02	129.90	79	102.40	99.01	3.38
2002-03 (Upto Jan.)	137.53	80	91 15	88.24	2.76

In addition, mini cement plants produce about 4 Million Tonnes of cement per annum, entire of which is consumed.

(d) The ongoing process of policy initiatives ensures that these remain conducive to both addition of new capacities and their better utilization for meeting the increasing demand for cement. Further, an additional capacity of 39 Million Tonnes is envisaged during the Tenth Plan period to meet the projected demand-supply gap.

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: Sir, the Government policy is that it will intervene only when certain members of the industry indulge in *malafide* trade practices to have a monopolistic control over production and price of cement, and thereby, disturb the balance between demand and supply. So, I would like to know from the hon. Minister the number of cases that have, so far, been filed during the last three years against the errand members of the industry, and the action that is being contemplated against such members of the industry. For example in our State, they have made a ring among themselves and by not making available adequate supplies, they are creating an artificial shortage. They are having less and less production and creating an artificial shortage of cement. Towards this end, what steps is the Government taking to fight against this cartelisation in the cement industry?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, with regard to cartelisation in the cement industry or any other industry, the existing framework is dealt with by the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, and there are two cases pending before the MRTP Commission. The total number of companies involved with regard to those cases is ten large—these are ten large companies. But that Act is eventually intended to be replaced by the Competition Act, which has already been approved and which has a more specific mechanism to deal with cartelisation. I may, however, inform the hon. Member that in the last few years, there has, by and large, been a surplus capacity; cement prices have been under control over the last four years. It is only in one particular year that this factor was noticed, during which period, the MRTP Commission had already intervened.

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: Sir, according to the reply to part (c) of my question, the production varies between one to two million tonnes, from 1999 to 2003. But the reality is that the domestic

cement industry is dominated by the private sector, which produces about 146 tonnes in more than 124 large plants in the country. The problem is that sometimes the demand is more, and some times the production is less. In this situation, the price of cement various from region to region. So, I would like to know from the hon. Member whether the Ministry has any mechanism, or any formula, whereby we can maintain a uniformity in the price of cement all over the country.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I think we are past that stage, when the problem of less production in cement existed. As I mentioned, there was reduction in the supply of cement only in one year, about two years ago. Barring that, in each year, the capacities have increased, and during the Tenth Plan period there is a further increase of capacities that is anticipated. A bulk of the cement production is in the private sector and there is a lot of competition today in the private sector, and it is that competition which is really holding the price line. Now, with regard to prices varying from State to States. The price variation depends upon the distance that the product has to cover to travel to that State and, secondly, upon any form of local taxation on the entry of cement in some of the states. For example, there are States, which are close to the production centres, where the prices are still reasonably low. For instance this year, in Jaipur, Rajasthan, the price per bage is about Rs. 118. But, there are other States, particularly in the Nort-East and Jammu and Kashmir where distances are large; and in addition to distances, on account of local taxation, prices are higher than what they should be.

डॉ॰ अबरार अहमद: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, इसमें एक सारणी दी है और इसमें एक इंस्टाल्ड कैपेसिटी बताई है। अगर इसको गहराई से देखें तो पाएंगे कि इंस्टाल्ड कैपेसिटी बराबर बढ़ रही है। इसके साथ ही जो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी दी है, वह घट रही है। प्रोडक्शन के बारे में बताया है कि बढा है लेकिन वह कंजम्शन के अनुपात में कम है, कंजम्शन बराबर बढ़ रहा है। अगर हम इसका विश्लेषण करें और प्रश्न के अंतिम भाग में जो मांग और पूंर्ति की बात है, इससे यह पता लगता है कि मांग अधिक है और पूर्ति कम हो रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है इंस्टाल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिट सिक हो रही हैं, इकाइयां बीमार हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश में कितने छोटे प्लांट हैं। और इनमें से कितने सिक पड़े हुए हैं? कितने बंद प्लांट हैं, उनमें से कितने सिक प्लांट हैं? महोदय, आपने देखा होगा कि कभी सवाई माधोपुर एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी। आज भी लोग उम्मीद लगाए बैठे

हैं कि इससे भी कभी धुआं निकलेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस फैक्ट्री की क्या स्थिति है? क्या वह भी कभी चल सकेगी?

श्री अरूण जेटली: सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि आज सीमेंट के क्षेत्र में काफी कम्पटिशन है और हर यूनिट को उस कम्पटिशन के वातावरण के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि इसी कम्पटिशन की वजह से पिछले चार वर्षों में सीमेंट की कीमतों पर नियंत्रण रहा है। यह जो सीमेंट की पैदावार की क्षमता बढ़ी है, यह केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ी है। इसीलिए अलग-अलग प्लांट की जो प्रोडक्शन है, वह इंस्टाल्ड कैपेसिटी से कम है। इसीलिए इस वर्ष वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अंदर जब 48 नए राज मार्गों की घोषणा की थी तो उसमें यह भी प्रावधान किया था कि इसमें 25 परसेंट वे होंगे, जो कंक्रीट से बनेंगे और उनमें सीमेंट का प्रयोग होगा ताकि पूरी इंस्टाल्ड कैपेसिटी उसमें उपयोग हो पाए। जहां मिनी सीमेंट प्लांट है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार के पास इनके आंकड़े नहीं आ पाते तो उसके बारे में अभी बतला पाना संभव नहीं है। बड़े प्लांट्स में लगभग 17 प्लांट ऐसे हैं, जो तकनीकी कारणों या फाइनेंस की वजह से प्रोडक्शन में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो दस प्लांट सीमेंट कारपोरेशन के हैं, जो पब्लिक सैक्टर में थे, उनमें से केवल तीन प्लान्ट आपरेट कर रहे हैं। इन तीन में से केवल एक प्रोफिट में है।

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, शायद मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी कि 2008 में, बीजिंग में ओलम्पिक होने वाला है, इसकी वजह से चाइना में हिन्दुस्तान का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चीन में भारतीय सामग्री का जो निर्यात हो रहा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मटीरियल का ज्यादा निर्यात हो रहा है। इसमें सीमेंट और स्टील सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपने बताया कि लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और पिछले साल जनवरी तक के एक्सपोर्ट का सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो 1999-2000 के बीच जो एक्सपोर्ट था, इसका डबल हो गया। ऐसी स्थिति में जायज बात है कि डिमांड बढ़ रही है और हमारा माल बाहर जा रहा है। जब माल बाहर जा रहा है, मेरे पास जानकारी के अनुसार चाइना में जो प्राइस लिया जा रहा है वह हिन्दुस्तानी प्राइज से कम है। कहीं ऐसा न हो वहां डिमांड बढ़े, जहां हमारा माल जा रहा है और यहां पर सप्लाई की जो क्राइसेस होगी उसकी वजह से सीमेंट के प्राइसेस बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हम प्राइसेज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नए सिनेरियो में आप प्राइसेस कंट्रोल करने की दिशा में क्या स्टेप उठा सकते हैं?

श्री अरूण जेटली: सभापति महोदय, जहां तक हमारे यहां सीमेंट इंडस्ट्री की जो एफिशिएन्सी है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो इन्टरनेशनल, कम्पेटेटिव स्टेंडर्ड्स के बहुत अनुकूल है। हमारे जितने भी प्लांट हैं, जितने भी मापदंड हैं, लेबर प्रोडेक्टिविटी का है, एनर्जी कंजम्शन का है, जितने इंटरनेशनल बैंच मार्क्स हैं उनको बीट कर रहे हैं। जहां तक एक्सपोर्ट के माध्यम से बाहर भेजने का प्रयास है, मैंने कहा कि सीमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कैपेसिटी काफी

बढ़ी है। इसलिए उसमें भी बहुत अधिक कम्पटिशन है। जैसे पिछले वर्ष 129 मिलियन टन की कैपेसिटी के अगेंस्ट अगर हमने 102 मिलियन टन की पैदावार की तो उसमें से केवल 5.14 मिलियन मीट्रिक टन था जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाए, लगभग पांच परसेंट के करीब। हिन्दुस्तान की जो सीमेंट कैपेसिटी है, यह दुनिया में सैकेन्ड लार्जेस्ट कैपेसिटी है। चाइना का आपने जिक्र किया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन यह भी मद्देनजर रखें कि चाइना एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी सीमेंट की कैपेसिटी हमसे ज्यादा है। हम दूसरे नम्बर पर हैं 129 मीट्रिक टन की साथ। चाईना की कैपेसिटी आज भी 750 मिलियन मीट्रिक टन है और साढे सात सौ के अगेन्स्ट् चाईना के अंदर जो प्रोडक्शन है, वह 600 मिलियन मीट्रिक टन का है। अपना माल दूसरे देशों में बेचने के लिए चाईना को भी यह कठिनाई आ रही है और 600 मिलियन मीट्रिक टन में से वह केवल 9 मिलियन मीट्रिक टन ही एक्सपोर्ट कर पाएगा।

Earnings of DD

*265. SHRI K. RAMA MOHANA RAO:††
SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the revenue earnings of Doordarshan during the last three years, year-wise;

(b) the steps being taken to re-organise the marketing system of Doordarshan; and

(c) the source of revenue of Doordarshan apart from advertisements?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Doordarshan has informed that it's total revenue (including commercial revenue) for the last three years is as follows:

1999-2000=Rs. 603,94,08,589
2000-2001=Rs.643,40,64,614
2001-2002=Rs. 622,87,22,397

(b) Various steps have been taken to reorganize the marketing system which include operationalization of Marketing Divisions at

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. Rama Mohana Rao.